

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

फ्लेवर्ड मिल्क पर जीएसटी: मद्रास एचसी का फैसला मोहित मिनरल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है



एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने, पारले एग्रो द्वारा सुगंधित दूध के वर्गीकरण को चुनौती देने वाली एक याचिका का जवाब देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की एक मिसाल का सहारा लिया, जिसमें कहा गया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। नोसितुर ए सोसाइटी के सिद्धांत को लागू करते हुए, अदालत ने निर्दिष्ट किया कि 'दूध युक्त पेय' विशेष रूप से पौधे या बीज-आधारित दूध को संदर्भित करता है, डेयरी दूध को नहीं।

स्वादयुक्त दूध को जीएसटी टैरिफ शीर्षक 0404 के तहत वर्गीकृत करते हुए, अदालत ने कर दर में संशोधन के लिए एक नई सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेषज्ञ विवादों में करदाताओं के लिए निर्णय के महत्व को पहचानते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की उम्मीद करते हैं। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने जीएसटी परिषद की चर्चाओं के आधार पर कर मांगों को चुनौती देने में फैसले के महत्व पर गौर किया।

हालाँकि, इसने कानूनी संशोधनों के माध्यम से ऐसे निर्णयों को लागू करने के सरकार के अधिकार पर प्रकाश डाला। लक्ष्मीकुमारन और श्रीधरन अटॉर्नीज़ के राघवन रामबद्रन ने अदालत के स्पष्टीकरण का स्वागत किया, इसे डेयरी उद्योग के लिए एक ताज़ा निर्णय बताया, कर स्थितियों को समायोजित करने से पहले गहन विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया।

सरकार ने मनरेगा और फसल बीमा में मजबूत वृद्धि की रिपोर्ट दी; पशुधन में एलएसडी को संबोधित करता है



5 दिसंबर, 2023 को एक हालिया संसदीय अपडेट में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने साझा किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने इस वर्ष 2,216 मिलियन मानव दिवसों का सृजन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो 2022-23 और 2021-22 के लिए साल-दर-साल क्रमशः 33.4% और 41% बढ़ रही है। खरीफ़ 2023 सीज़न में किसान आवेदनों में उल्लेखनीय 28.9% की वृद्धि और बीमित क्षेत्र में 24% की वृद्धि देखी गई।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, परषोत्तम रूपाला ने पशुधन में गांठदार त्वचा रोग की चिंता को संबोधित किया, जिसमें 2023 में कुल 73,390 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 16,302 वर्तमान में सक्रिय मामले हैं। सरकार ग्रामीण और डेयरी क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए अपना व्यापक दृष्टिकोण जारी रखे हुए है।

जीएफ में एनडीडीबी स्टॉल ने जातीय-पशु चिकित्सा प्रथाओं की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला



यह स्टॉल किसानों को मवेशियों के लिए हर्बल औषधि के लाभों के बारे में शिक्षित करता है, एंटीबायोटिक दवाओं का सहारा लिए बिना बीमारी की रोकथाम में सहायता करता है। एनडीडीबी का लक्ष्य पशु कल्याण को बढ़ाना, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित दूध सुनिश्चित करना है।

केरल का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) चल रहे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव (जीएफ-2023) में मवेशियों के लिए स्वदेशी दवाओं के कुशल उपयोग पर जोर देता है। पारंपरिक जातीय-पशुचिकित्सा प्रथाओं को बढ़ावा देना एनडीडीबी के 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो लोगों, जानवरों और पर्यावरण के लिए इष्टतम स्वास्थ्य के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की वकालत करता है।

केरल के योगदान को स्वीकार करते हुए, स्टाल में जड़ी-बूटियों के नाम और मिश्रणों की मात्रा का विवरण दिया गया है। एनडीडीबी के उप निदेशक रोमी जैकब ने मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला और देश भर में डेयरी सहकारी समितियों में जातीय-पशु चिकित्सा प्रथाओं को अपनाने में वृद्धि पर ध्यान दिया।

2022-23 में दूध उत्पादन 4% बढ़कर 230.58 मिलियन टन: सरकार

सरकार ने रविवार को कहा कि 2022-23 में भारत का दूध उत्पादन 4 प्रतिशत बढ़कर 230.58 मिलियन टन हो गया, जबकि अंडे का उत्पादन 7 प्रतिशत बढ़कर 138.38 बिलियन टन हो गया। 2022-23 के दौरान मांस का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत बढ़कर 9.77 मिलियन टन हो गया।



केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कार्यक्रम में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 (दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन 2022-23) जारी किया। रूपाला ने बताया कि 2022-23 के दौरान देश में कुल दूध उत्पादन 230.58 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2021-22 के अनुमान से 3.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पूर्व में, 2018-19 में वार्षिक वृद्धि दर 6.47 प्रतिशत थी; 2019-20 में 5.69 प्रतिशत; 2020-21 में 5.81 प्रतिशत और 2021-22 में 5.77 प्रतिशत। रूपाला ने कहा कि 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72 प्रतिशत थी, इसके बाद राजस्थान (14.44 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (8.73 प्रतिशत), गुजरात (7.49 प्रतिशत) थे। , और आंध्र प्रदेश (6.70 प्रतिशत)। वार्षिक वृद्धि दर के मामले में, कर्नाटक ने पिछले वर्ष की तुलना में 8.76 प्रतिशत की उच्चतम दर हासिल की, इसके बाद पश्चिम बंगाल (8.65 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (6.99 प्रतिशत) का स्थान रहा। 2022-23 में अंडे का उत्पादन 138.38 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2018-19 में 103.80 बिलियन से 33.31 प्रतिशत अधिक है। 2021-22 की तुलना में 2022-23 में अंडे का उत्पादन सालाना 6.77 प्रतिशत बढ़ा

पीएम गतिशक्ति के तहत 61वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक



पीएम गतिशक्ति के तत्वावधान में 61वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) की बैठक में राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के दो साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। श्रीमती की अध्यक्षता में डीपीआईआईटी की विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) सुमिता डावरा ने सत्र में आर्थिक क्षेत्रों और 100 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मानचित्रण की प्रगति की समीक्षा की। प्रमुख मंत्रालयों के 60 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें 39 मंत्रालयों, 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करने और 'पीएम गतिशक्ति के संग्रह' को लॉन्च करने जैसी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया।

एनएमपी, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान और प्राथमिकता में सहायता के लिए, रुपये का बजट आवंटन देखा गया। वित्त वर्ष 2023-24 में 75,000 करोड़। विशेष सचिव डावरा ने 1300 से अधिक परिकल्पित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक योजना और समावेशी विकास पर जोर दिया।

विभिन्न मंत्रालयों ने मल्टीमॉडलिटी और अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में पोर्टल की प्रभावकारिता पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी। पीएम गतिशक्ति पहल निर्बाध आर्थिक गतिविधियों और कुशल लॉजिस्टिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में उभरी है।

हम कौन हैं?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि कौशल परिषद (ASCI) के तत्वावधान में काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था "सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)", किसानों की आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करने के लिए, वेतनभोगी कर्मचारी, और डेयरी मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारक।

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

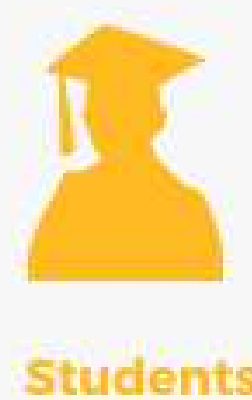


Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- ✓ Platform to interact with other members in the sector
- ✓ Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- ✓ Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- ✓ Access to our Journal and Publications
- ✓ Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- ✓ Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- ✓ Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- ✓ Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- ✓ Consultative and advisory services to help members
- ✓ Consulting and advisory services to help members
- ✓ Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- ✓ Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -



CEDSI : रविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी